मद्रास राज्य

बनाम

ए. वैद्यनाथ अय्यर

(बी.पी. सिन्हा, गोविंदा मेनन और जे.एल. कपूर, जेजे.)

विशेष अनुमति द्वारा अपील-सर्वोच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की शक्ति द्वारा बरी करने का आदेश-पूर्वधारणा-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। (1947 का द्वितीय), धारा 4-भारत का संविधान, अनुच्छेद 136।

प्रत्यर्थी, एक आयकर अधिकारी, ने एक निर्धारिती को अपने घर बुलाया और उनसे 800 रुपये की राशि ली। इसके तुरंत बाद तलाशी ली गई और प्रतिवादी ने कुछ चोरी के बाद पैसे जमा किए। प्रत्यर्थी का बचाव यह था कि उसने पैसे को ऋण के रूप में लिया था न कि अवैध संतुष्टि के रूप में। प्रतिवादी पर मुकदमा चलाने वाले विशेष न्यायाधीश ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत दोषी पाया और उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अपील पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को बरी कर दिया। राज्य ने विशेष अनुमति ली और अपील की।

माना जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 136 में उपयोग किए जाने वाले शब्द से पता चलता है कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि के निर्णय

और बरी किए जाने के निर्णय के बीच निर्माण के मामले के रूप में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय तब तक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्षों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यदि उच्च न्यायालय विकृत या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य करता है तो हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष रुक रहे हैं और मामले में उसका दृष्टिकोण गलत रहा है क्योंकि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1947 का द्वितीय) की धारा 4 के तहत सबूत के बोझ के विशेष नियम की अवहेलना की है। उच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि साक्ष्य के कुछ मुख्य अंश छूट गए थे या उनकी उचित रूप से सराहना नहीं की गई थी।

इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति द्वारा अपील में हस्तक्षेप कर सकता है।

जहाँ यह साबित हो जाता है कि संतुष्टि स्वीकार कर ली गई है, वहाँ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुमान तुरंत उत्पन्न होगा। यह कानून की एक धारणा है और धारा 4 के तहत लाए गए प्रत्येक मामले में इसे उठाना न्यायालय के लिए अनिवार्य है।

इस मामले में साक्ष्य और परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकलता है कि लेन-देन ऋण का नहीं बल्कि अवैध संतुष्टि का था।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं. 5/1957।

1954 की आपराधिक अपील संख्या 498 और 1955 की आपराधिक पुनरीक्षण मामले संख्या 257 में मद्रास उच्च न्यायालय के 6 सितंबर, 1955 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील, 1952 की सी. सी. संख्या 1 में विशेष न्यायाधीश, कोयंबटूर के 12 जुलाई, 1954 के फैसले और आदेश से उत्पन्न हुई।

अपीलार्थियों के लिए एच.जे. उमरीगर, एच.आर. खन्ना और आर.एच. ढेबर।

प्रतिवादी के लिए के.एस. कृष्णस्वामी अयंगर और सरदार बहादुर।

26 सितंबर 1957।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय कपूर जे. द्वारा दिया गया था।

यह मद्रास राज्य द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के खिलाफ एक अपील है, जिसमें कोयंबटूर के विशेष न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया गया था और इस तरह प्रत्यर्थी को बरी कर दिया गया था,

जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। और छह महीने के साधारण कारावास की सजा।

प्रत्यर्थी, वैद्यनाथ अय्यर, हर समय कोयम्बटूर के आयकर अधिकारी थे और यह विवादित नहीं है कि वे जून 1951 की शुरुआत में वहां थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार सितंबर 1951 के अंत में प्रतिवादी ने के. एस. नारायण अय्यर (जिसे इसके बाद शिकायतकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) से 1000 रुपए रिश्वत की मांग की, जो कोयंबटूर में नेहरू कैफे नामक "कॉफी होटल" के मालिक हैं और भवानीसागर में इसी तरह के एक अन्य होटल के मालिक हैं।

शिकायतकर्ता पर 1942 से आयकर लगाया जा रहा था। वर्ष 1950-51 के मूल्यांकन के दौरान यह पता चला कि वह अग्रिम आयकर का भुगतान करने में विफल रहा था। इसलिए 24 मार्च, 1951 को उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 18-ए (2) के साथ पठित धारा 28 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था ताकि यह बताया जा सके कि उनकी आय को कम आंकने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। निर्धारण वर्ष 1951-52 के लिए भी शिकायतकर्ता ने सामान्य रूप से 11 अगस्त, 1951 को अपना विवरणी दाखिल किया और उसे नोटिस जारी होने पर 27 सितंबर, 1951 को आयकर अधिकारी के समक्ष अपने खाते पेश किए। वह 28 तारीख को फिर से उसके सामने पेश हुआ और प्रतिवादी ने उसे बताया

कि "जुर्माने के कागजात का निपटारा नहीं किया गया है और चालू वर्ष के खातों को भी नहीं देखा गया है" और शिकायतकर्ता को अगली सुबह उसे अपने घर पर देखने के लिए कहा, जो शिकायतकर्ता ने किया। वहाँ प्रत्यर्थी ने उससे कहा कि यदि वह चाहता है कि उसकी वापसी स्वीकार की जाए और दंड कार्यवाही के मामले में उसकी मदद की जाए तो उसे प्रत्यर्थी को रु. 1,000 दिये अवैध संतुष्टि के रूप में। शिकायतकर्ता ने अपने प्रबंधक को इस तथ्य का उल्लेख किया और यह भी कि उसे आयकर अधिकारी ने बताया था कि उसके खाते असंतोषजनक थे। क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था, शिकायतकर्ता ने 6 या 7 अक्टूबर को प्रतिवादी को उसके घर पर देखा और उसने शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह पैसे लेकर आया है और मूल्यांकन के बारे में कुछ बात करने के बाद प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से आधी राशि का भुगतान करने के लिए कहा क्योंकि यह दीपावली का समय था। बचाव पक्ष के गवाह के पास यह दिखाने के लिए भी सबूत है कि अक्टूबर 1951 के अंत में, शिकायतकर्ता को प्रतिवादी के घर से आते देखा गया था, हालांकि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में सहमत नहीं हैं।

सर्कल इंस्पेक्टर, मुनिसामी पी. डब्ल्यू. 12, का दावा है कि मद्रास में रहते हुए उन्हें प्रतिवादी के भ्रष्ट होने और "भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त होने" के बारे में शिकायतें मिलीं। इसके बाद वह कोयंबटूर आया और शिकायतकर्ता

से संपर्क किया और उससे पूछा कि क्या उसने प्रतिवादी को कोई रिश्वत दी है। शिकायतकर्ता ने इंस्पेक्टर को प्रतिवादी द्वारा रिश्वत की मांग के बारे में बताया इंस्पेक्टर के कहने पर शिकायतकर्ता तहसीलदार-मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ, जिन्होंने अपना बयान पी-17 दर्ज किया, जिसमें रिश्वत की मांग की पूरी कहानी बताई गई है। इसके बाद इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता को दस सौ के नोट दिए, जब एक्स में उनके नंबर हटा लिए गए। पी-17 शिकायतकर्ता तब अभियुक्त के कार्यालय गया लेकिन उस दिन कोई पैसा स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि प्रतिवादी को एक गुमनाम पत्र पूर्व प्राप्त हुआ था। पी-18 ने उन्हें उस जाल के बारे में चेतावनी दी जो मलयालम लोगों द्वारा बिछाया जा रहा था। स्वाभाविक रूप से प्रतिवादी शिकायतकर्ता से बहुत नाराज हो गया और उसे दूर भेज दिया। उसी शाम शिकायतकर्ता को बताया गया कि उसे अगली सुबह प्रत्यर्थी के घर जाना है जो उसने सुबह 8 बजे किया। प्रत्यर्थी ने उससे कहा कि उसे उस गुमनाम पत्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो उसके दुश्मनों द्वारा भेजा गया होगा और उसे कुछ पैसे देने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने रुपये की राशि का भुगतान किया। 200 जिसे लौटने पर उन्होंने अपनी कच लेखा पुस्तिका में दर्ज किया जिसे उच्च न्यायालय ने बिना किसी पर्याप्त कारण के खारिज कर दिया। 15 नवंबर, 2010 की शाम को शिकायतकर्ता फिर से प्रतिवादी के घर गया और बाद वाले ने उससे कहा कि वह अंतिम आदेश पारित करेगा और पैसे का भुगतान किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड, पी-7 और पी-7 (ए) से

पता चलता है कि 13 नवंबर को एक आदेश दिया गया था, हालांकि इस बात का कोई सबूत या संकेत भी नहीं है कि शिकायतकर्ता को इसके बारे में पता था। शिकायतकर्ता को निरीक्षक द्वारा 8 सौ रुपये के नोट दिए गए और शिकायतकर्ता ने उन्हें 17 नवंबर की सुबह प्रतिवादी को उसके घर पर भुगतान कर दिया। इस अवसर पर शिकायतकर्ता अपने प्रबंधक पी. डब्ल्यू. 14 के साथ मजिस्ट्रेट और सर्कल इंस्पेक्टर और वेंकटेश आई. अय्यर पी. डब्ल्यू. 14 के साथ एक कार में प्रतिवादी के घर की ओर गया था जिसे प्रतिवादी के घर से तीन या चार ब्लॉक दूर रोका गया था और केवल शिकायतकर्ता और उसका प्रबंधक प्रतिवादी के घर में गए और पैसे का भुगतान किया। दू या तीन मिनट बाद इंस्पेक्टर पीडब्लू 12 और मजिस्ट्रेट पीडब्लू 13 और एक सेशा अय्यर जो रास्ते में पार्टी में शामिल हुए थे, शिकायतकर्ता से संकेत मिलने पर घर में आए। उन्होंने प्रतिवादी को अपनी पहचान बताई और उन्हें बताया कि उन्हें जानकारी है कि उन्हें रुपये मिले हैं। शिकायतकर्ता से अवैध संतुष्टि के रूप में 800 और उसे शिकायतकर्ता से प्राप्त धन को प्रस्तुत करने के लिए कहा। प्रत्यर्थी ने कुछ नहीं कहा और जिस कुर्सी पर वह बैठा था, उससे उठा और घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और फिर उसने अपनी धोती की तहों से पैसे निकाल लिए। जब मजार तैयार किया जा रहा था तो प्रतिवादी ने कहा कि उसे यह पैसा शिकायतकर्ता से ऋण के रूप में मिला था, जिसने इससे इनकार किया और कहा कि इसे रिश्वत के रूप में दिया

गया था। इसके बाद विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक को एक तार भेजा गया और उनके आदेश के तहत एक मामला दर्ज किया गया और फिर एक पुलिस उपाधीक्षक द्वारा जांच शुरू की गई, जिन्होंने 19 नवंबर को प्रतिवादी के घर की तलाशी ली, लेकिन ऐसा लगता है कि उस तारीख को कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ या उसे अपने कब्जे में नहीं लिया गया। बाद में प्रत्यर्थी द्वारा 17 जुलाई, 1952 को एस के तहत अपने बयान के दौरान चार अन्न टिकटों के साथ एक उच्चारण अदालत में पेश किया गया था। 342 दंड प्रक्रिया संहिता लेकिन प्रतिवादी द्वारा मजिस्ट्रेट पी. डब्ल्यू. 13 को इसका उल्लेख नहीं किया गया था।

प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता से 800 रु आधिकारिक कार्यों के प्रयोग में उसे अनुग्रह दिखाने के लिए पुरस्कार के उद्देश्य के रूप में कानूनी पारिश्रमिक के अलावा संतुष्टि के रूप में और इस तरह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (47 का अधिनियम II) की धारा 4 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत दंडनीय अपराध किया था।

प्रत्यर्थी का स्पष्टीकरण यह था कि उसने शिकायतकर्ता को अपनी धन कठिनाइयों के बारे में बताया जब वह अगस्त के अंत या सितंबर 1951 की शुरुआत में सड़क पर गलती से उससे मिला। शिकायतकर्ता ने उसे 1,000/- रुपये उधार देने की पेशकश की। उस समय उन्हें इस बात

की जानकारी नहीं थी कि शिकायतकर्ता का मूल्यांकन उनके समक्ष लंबित है। यह शिकायतकर्ता ही था जिसने 15 नवंबर को उसे बताया था जब वह उससे फिर मिला था कि गुमनाम पत्र "उसके दुश्मनों का काम" था और उसने पहले किए गए वादे के अनुसार ऋण को आगे बढ़ाने का वादा किया था और उसने यह भी सुझाव दिया था कि प्रतिवादी को 1, 000 रुपये के लिए निष्पादित करना चाहिए जिसे वेंकटेश अय्यर द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसके लिए वह (प्रतिवादी) सहमत थे। शिकायतकर्ता ने 800 रुपये का भुगतान 17 नवंबर की सुबह किया और शाम 200 रुपये देने का वादा किया। प्रत्यर्थी ने प्रोनोट तैयार कर लिया था और सुबह उसे सौंपने की पेशकश की, लेकिन शिकायतकर्ता ने कहा कि जब वह "घर से बाहर निकलेगा" तो वह इसे ले जाएगा।

विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार कर लिया और साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद प्रतिवादी को आरोपित अपराध का दोषी पाया और उसे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

उच्च न्यायालय में अपील किए जाने पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने फैसले को उलट दिया और प्रतिवादी को बरी कर दिया। विद्वान न्यायाधीश के मुख्य निष्कर्षों को उनके अपने शब्दों में यहाँ देना सुविधाजनक होगाः

(i) "यह सच है कि उस समय जब अभियुक्त द्वारा धन स्वीकार किया गया था, पीडब्लू 8 पर आयकर के आकलन के संबंध में कार्यवाही अभियुक्तों के समक्ष विचाराधीन थे। स्वाभाविक रूप से, इसलिए, यदि ऐसी परिस्थितियों में, अभियुक्त को किसी निर्धारिती से धन प्राप्त होना चाहिए, तो यह संदेह तुरंत पैदा हो जाता है कि धन का भुगतान केवल अवैध संतुष्टि के रूप में किया गया होगा। विद्वत विचारण न्यायाधीश के निर्णय को देखने पर, मैंने यह धारणा बनाई कि वह इस तरह के संदेह से पूरी तरह से प्रभावित था।

(ii) "परिणाम यह है कि यदि पी. डब्ल्यू. 8 और अभियुक्त के संस्करण संतुलित हैं, तो संभावना अभियुक्त के संस्करण के पक्ष में पैमाने को झुकाती प्रतीत होती है। किसी भी मामले में, साक्ष्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण उचित रूप से सच नहीं हो सकता है, और इसलिए, संदेह का लाभ उसे मिलना चाहिए।

(iii) "लेकिन यह सामान्य ऋणदाता का मामला नहीं था, बल्कि एक आयकर अधिकारी का मामला था, जिसके पक्ष की ऋणदाता को आवश्यकता थी।

(iv) "साक्ष्य से पता चलता है कि नवंबर, 1951 में अभियुक्त को 1, 000 रुपये की राशि की आवश्यकता थी। और, उस उद्देश्य के लिए, पी. डब्ल्यू. 8 से ऋण की मांग करी।

(v) "मेरे विचार में, साक्ष्य आवश्यक रूप से इस बात को आसान नहीं बनाता है कि अभियुक्त ने पैसे को केवल रिश्वत के रूप में स्वीकार किया होगा।

(vi) "इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि ब्याज के साथ इसे चुकाने के दायित्व के साथ ऋण लेना, 'संतुष्टि' शब्द के अर्थ के भीतर आएगा।

बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की सीमा प्रत्यर्थी के वकील द्वारा हमारे सामने रखी गई थी और यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 186 के तहत इस अदालत द्वारा प्रयोग की गई अधिकारिता वही थी जो प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा प्रयोग की गई थी और वेंकट-राम अय्यर जे द्वारा अहेर राजा खीमा बनाम में अल्पमत निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी।

> "प्रारंभिक परिच्छेद में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती अनुच्छेद स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 134 है। अनुच्छेद 134 (1) इस न्यायालय को अपील करने का अधिकार प्रदान करता है-कुछ मामलों में, अयोग्य, तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर, और यदि अनुच्छेद 136 के तहत अपील का दायरा तथ्य के प्रश्नों के लिए इसी तरह बढ़ाया जाना है, तो अनुच्छेद 134 (1) अनावश्यक हो जाएगा। यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 134 (1) (ए) और (बी) के तहत तथ्यों पर अपील का प्रावधान करने

में संविधान का इरादा इसे अनुच्छेद 136 के तहत बाहर करना था, और यह प्रीतम सिंह बनाम राज्य में पहुंचे निष्कर्ष का दृढ़ता से समर्थन करता है कि प्रिवी काउंसिल की तरह यह न्यायालय आपराधिक मामले में तथ्यों पर अपील के लिए आगे की अदालत के रूप में कार्य नहीं करेगा।"

मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण गणपतराव लिम्से (1) का भी प्रत्यर्थी के वकील द्वारा उल्लेख किया गया था और यह तर्क दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को केवल इस आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि वह तथ्यों के बारे में एक अलग दृष्टिकोण रखता है। यह एक ऐसी अपील थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र पर लाया गया था न कि इस न्यायालय की विशेष अनुमति से। उस फैसले पर मद्रास राज्य बनाम गुरवैया नायडू एंड कंपनी लिमिटेड की संविधान पीठ ने विचार किया था। (2) और कार्यवाहक सी. जे. एस. आर. दास ने न्यायालय का निर्णय देते हुए कहा कि यह तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था न कि संविधान पीठ का और यह टिप्पणी कि धाराओं के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 में केवल इस बात पर जोर दिया गया है कि इस न्यायालय को विशेष अनुमति द्वारा अपील में केवल तथ्य या कानून की त्रुटियों को सुधारने के

लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गुरवैया नायडू का मामला (2) बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ एक अपील थी और इस अदालत ने यह कहते हुए फैसले को उलट दियाः

हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को स्थापित करने और अभियुक्तों को बरी करने में विफल रहा।

यह मामला इस तर्क को नकारता है कि अनुच्छेद 136 के तहत इस अदालत द्वारा बरी करने के निर्णयों में उच्च न्यायालयों के निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण गणपतराव (1) मामले में भी न्यायमूर्ति महाजन की राय थी कि उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है जहां उच्च न्यायालय "विकृत रूप से या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य करता है या धोखाधड़ी से धोखा दिया गया है।"

प्रीतम सिंह बनाम राज्य (3) फ़ज़ल अली जे. में अनुच्छेद 136 की सावधानीपूर्वक जांच के बाद पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के साथ अनुच्छेद 136 के तहत अपील का दायरा इस प्रकार बताया गया हैः

"आम तौर पर, यह अदालत विशेष अनुमति नहीं देगी, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि असाधारण और विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं, कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय किया गया है और यह कि विचाराधीन मामला निर्णय की समीक्षा के लिए पर्याप्त गंभीरता की विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। यहां तक कि आपराधिक मामलों में समीक्षा के लिए अनुमेय सीमाएं निर्धारित करने में प्रिवी काउंसिल में ऐसी चीजें शामिल थीं जो "इतनी अनियमित या इतनी अपमानजनक थीं कि न्याय के आधार को ही झटका दे सकती थीं।" मोहिंदर सिंह बनाम राजा (1) देखें।

इस सिद्धांत का एक उदाहरण स्टीफन सेनेविरत्ने बनाम राजा (2) में प्रिवी काउंसिल का निर्णय है, जिस पर बाद में इस फैसले में चर्चा की जाएगी और जिसे इस अदालत द्वारा अनुमोदित किया गया है।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 205 के निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करते हुए, "किसी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश" और "यह ब्रिटिश भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक मामले में विचार करे", लॉर्ड थैंकर्टन ने किंग एम्परर बनाम सिबनाथ बनर्जी (') में कहाः-"प्रावधान का उद्देश्य प्रत्येक मामले में अपील का अधिकार प्रदान करना है जिसमें अधिनियम या उसके

तहत बनाए गए किसी भी आदेश की व्याख्या के रूप में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।" उस मामले में निर्णय के लिए प्रश्नों में से एक यह था कि क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों में अपील की जाती है। लॉर्ड थैंकर्टन ने वहाँ कहाः "बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों के एक स्पष्ट अपवाद के अभाव में, और धारा के नियमों और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वामी केवल निर्माण द्वारा धारा की शर्तों को सीमित करने में असमर्थ हैं ताकि इन मामलों को इसके संचालन से बाहर रखा जा सके।"

अनुच्छेद 136 "उच्चतम न्यायालय अपने विवेकाधिकार में भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए किसी भी कारण या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है" शब्दों का उपयोग दर्शाता है कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि या बरी होने के फैसले के बीच निर्माण के मामले के रूप में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। भगवान दास बनाम राजस्थान राज्य (4) में पृष्ठ 299 पर स्टीफन एफ सेनेविरत्ने बनाम राजा (2) में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति की निम्नलिखित टिप्पणीः

> "....समग्र रूप से लिए गए साक्ष्य पर यहां कोई आधार नहीं है, जिस पर कोई भी न्यायाधिकरण वैध निष्कर्ष के मामले में उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि

अपीलार्थी दोषी था। "अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के फैसले को उलट दिया। वर्तमान मामले में निर्णय के लिए सवाल यह है कि क्या यह उपर्युक्त मामलों में निर्धारित सीमाओं के भीतर आता है। यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्षों में आसानी से हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन यदि उच्च न्यायालय प्रतिकूल या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य करता है तो हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।"

वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष, कम से कम कहने के लिए, रुकने वाले हैं, और पूरे प्रश्न का दृष्टिकोण ऐसा रहा है कि यह मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामकृष्ण गणपतराव (1) में श्री न्यायमूर्ति महाजन द्वारा "प्रतिकूल या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य करना" के रूप में वर्णित के अंतर्गत आता है। यद्यपि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय की शुरुआत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (1947 का द्वितीय) की धारा 4 के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा का उल्लेख किया है, निर्णय में निम्नलिखित अंशः "किसी भी मामले में, साक्ष्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण यथोचित रूप से सच नहीं

हो सकता है, और इसलिए, संदेह का लाभ उसे मिलना चाहिए।" यह उस धारणा की अवहेलना का संकेत है जिसे कानून को धारा 4 के तहत उठाने की आवश्यकता है। इस धारा के प्रासंगिक शब्द हैंः "जहां धारा 161 के तहत दंडनीय अपराध के किसी भी मुकदमे में।

इसलिए जहां यह साबित हो जाता है कि संतुष्टि स्वीकार कर ली गई है, तो धारा के तहत तुरंत धारणा उत्पन्न होगी। यह आपराधिक मामलों में सबूत के बोझ के रूप में सामान्य नियम के लिए एक अपवाद पेश करता है और आरोपी पर जिम्मेदारी डालता है। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि विधायिका ने 'अनुमान लगाएगी' शब्दों का उपयोग करने का विकल्प चुना है न कि 'पूर्व को कानून की धारणा और तथ्य की धारणा'। इन दोनों वाक्यांशों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस अधिनियम के उद्देश्य के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 साक्ष्य अधिनियम के समान है क्योंकि यह साक्ष्य के कानून की एक शाखा से संबंधित है, उदाहरण के लिए, अनुमान, और इसलिए इसका एक ही अर्थ होना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम में "मान लिया जाएगा" को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः "जब भी इस अधिनियम द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय किसी तथ्य को मान लेगा, तो वह ऐसे तथ्य को तब तक साबित मानता है जब तक कि इसे गलत नहीं माना जाता है।"

यह कानून का एक अनुमान है और इसलिए अदालत पर यह अनिवार्य है कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत लाए गए प्रत्येक मामले में इस अनुमान को उठाए क्योंकि तथ्य के अनुमानों के मामले के विपरीत, कानून के अनुमान न्यायशास्त्र की एक शाखा का गठन करते हैं। ऊपर उद्धृत निष्कर्ष देते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश ने धारा 4 के तहत सबूत के बोझ के विशेष नियम की अवहेलना की है और इसलिए इस मामले में उनका दृष्टिकोण गलत है।

निर्णय से यह भी पता चलता है कि साक्ष्य के कुछ मुख्य टुकड़े छूट गए थे या उनकी उचित रूप से सराहना नहीं की गई थी।

उस समय जब आयकर अधिनियम की धारा 28 के तहत जुर्माना नोटिस जारी किया गया था प्रतिवादी कोयंबटूर में आयकर अधिकारी नहीं था, लेकिन 6 जून तक उसे कोयंबटूर में तैनात कर दिया गया था और 6 जून, 1951 की पेनल्टी फाइल पर लिखा थाः "मानक जुर्माना लगाने के लिए आई.ए.सी. को प्रस्ताव दें", उनके द्वारा बनाया गया था। हालाँकि यह प्रस्ताव 6 जून, 1951 को दिया गया था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन कार्यवाही में कौन से अंतिम आदेश पारित किए गए थे और कब। कम से कम इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि इस मामले के संबंध में शिकायतकर्ता को कोई सूचना दी गई थी। शिकायतकर्ता ने पी. डब्ल्यू. 8 के रूप में शपथ ली हैः

"28 सितंबर, 1951 को मैं अकेला आरोपी के पास गया था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि दंड पत्र का निपटारा नहीं किया गया था और चालू वर्ष के खातों को भी नहीं देखा गया था। इसके अगले दिन प्रत्यर्थी ने शिकायतकर्ता से 1, 000 रुपये की अवैध संतुष्टि के लिए कहा। प्रत्यर्थी के वकील ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी के लिए दंड की कार्यवाही के बारे में कुछ भी कहने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि जहां तक उसका संबंध है, उसके द्वारा पहले ही सिफारिश की जा चुकी थी, लेकिन वास्तविक सवाल यह है कि क्या शिकायतकर्ता को बताया गया था कि क्या हुआ था या उसे इसकी कोई जानकारी थी। वह कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं था और यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसके पास था।

प्रत्यर्थी ने तब कहा है कि शिकायतकर्ता उसे 1942 से जानता था जब वह, प्रत्यर्थी, आयकर के अपीलीय सहायक आयुक्त का प्रमुख लिपिक था और यही कारण है कि अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में जब वह सड़क पर शिकायतकर्ता से अचानक मिला, तो उसने उसे बताया कि वह वित्तीय कठिनाइयों में था और शिकायतकर्ता ने उसे 1,

000 रुपये का ऋण देने की पेशकश की और कहा कि आसान किश्तों में वापस किया जाएगा और उस समय उसे पता नहीं था कि शिकायतकर्ता उसके सामने एक निर्धारिती था। उत्तरदाता के इस कथन को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किए बिना स्वीकार कर लिया है। शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया और उन्होंने 11 अगस्त, 1951 को अपना रिटर्न दाखिल किया। शिकायतकर्ता को नोटिस स्वयं प्रतिवादी द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 22 (2) के तहत जारी किया गया होना चाहिए क्योंकि वह उस समय आयकर अधिकारी था। इसलिए उसके इस बयान पर विश्वास करना मुश्किल है कि उसे यह नहीं पता था कि शिकायतकर्ता उससे पहले एक निर्धारिती था और यह असंभव है कि प्रतिवादी अपनी वित्तीय परेशानियों का उल्लेख किसी ऐसे परिचित से करेगा जिसे न तो बैंकर दिखाया गया है, न ही एक साहूकार और न ही एक अमीर व्यक्ति। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह 6 या 7 अक्टूबर 1951 को प्रतिवादी से मिलने गया था, जब उसने उससे पूछा कि क्या वह पैसे लाया है। शिकायतकर्ता ने जवाब दिया कि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि उसने एक घर खरीदा है और उसने उससे यह भी

पूछा कि क्या प्रतिवादी ने मूल्यांकन पूरा कर लिया है। बाद वाले का जवाब था कि वह मामले को देखेंगे और उनसे यह भी कहा कि शिकायतकर्ता दीपावली के समय से पहले आधी राशि (अवैध संतुष्टि की) का भुगतान कर सकता है। प्रत्यर्थी ने इस बयान से इनकार किया है, लेकिन शिकायतकर्ता के इस बयान को जिरह में गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है कि उसके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उसने एक घर खरीदा था।"

शिकायतकर्ता को खाते पेश करने के लिए कहा गया था और उसने उन्हें 27 सितंबर को पेश किया था। पी-7 और पी-7 (ए) में प्रतिवादी द्वारा किए गए नोटों से पता चलता है कि कोयंबटूर होटल के संबंध में शिकायतकर्ता के खातों को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। आदेश का हिस्सा थाः -

"होटल खातों में सामान्य रूप से होने वाले सभी दोष यहां मौजूद हैं।

भवानीसागर होटल के संबंध में नोट में कहा गया हैः "खरीद पूरी तरह से समर्थित नहीं है और बिक्री की गणना आय तक की जाती है।"

1 अक्टूबर, 1951 को निर्धारिती ने अपना लिखित बयान और कुछ अन्य दस्तावेज भी दाखिल किए थे। ऐसा लगता है कि 7 नवंबर तक और

कुछ नहीं किया गया है, जब फाइल पर नोट का प्रासंगिक हिस्सा हैः "मैं इसे पास के अन्य होटलों के साथ परिणामों की तुलना करने के लिए रख रहा हूं।"

इस बारे में कि इस पूरी अवधि में कोई पूछताछ क्यों नहीं की जा सकी, मूल्यांकन रिकॉर्ड से स्पष्ट नहीं है और यह अभियोजन पक्ष के मामले को समर्थन देता है कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता से पैसे लेने के लिए संपर्क कर रहा था। प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता की मूल्यांकन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को उसके घर जाने की अनुमति दी और यहां तक कि उसके कैफे में भी जाने की अनुमति दी। यहां तक कि उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के अनुसार शिकायतकर्ता को प्रत्यर्थी के "अनुग्रह की आवश्यकता" थी, जिसे अपने स्वयं के प्रदर्शन पर एक हजार रुपये की सख्त आवश्यकता थी क्योंकि वह 2 नवंबर तक केवल एक हजार रुपये एकत्र करने में सफल रहा था, और अपने बेटे के प्रीमियम या प्रतिभूति के लिए दोगुनी राशि की आवश्यकता थी क्योंकि वह इसे बुलाना चाहता है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा मामले के इस पहलू को कोई महत्व नहीं दिया गया था। हमारी राय में विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के मामले के इस हिस्से की सही सराहना की और उनका निर्णय, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है, केवल संदेह से भरा नहीं है।

6 नवंबर, 1951 को सर्कल इंस्पेक्टर मुनिसामी ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और 1, 000 की व्यवस्था की गई। इसका भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को किया जाना था और वास्तव में शिकायतकर्ता द्वारा पैसा लिया गया था, और 8 नवंबर को प्रत्यर्थी को पेश किया गया था जिसे प्रत्यर्थी ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसे एक गुमनाम पत्र पूर्व प्राप्त हुआ था। पी-18, जो 6 नवंबर, 1951 का था, जिसमें प्रतिवादी को चेतावनी दी गई थी कि मलयामी लोग उसे "बर्बाद" करने का प्रयास कर रहे थे। इस चेतावनी के बावजूद प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता के साथ ट्रक रखना जारी रखा और वास्तव में उनसे 800 रुपये स्वीकार किए। यह सच है कि जब पैसे का भुगतान किए जाने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर पीडब्ल्यू 12 और मजिस्ट्रेट पीडब्ल्यू 13 प्रतिवादी के घर पहुंचे और उससे इस पैसे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसने इसे ऋण के रूप में लिया था, लेकिन इस संदर्भ में यह अलग धारणा है।

मजिस्ट्रेट पी. डब्ल्यू. 13 का बयान थाः - "जब मजार तैयार किया जा रहा था तो आरोपी ने स्वेच्छा से मुझे बताया कि उसे शिकायतकर्ता पीडब्लू 8 से 800 रुपये ऋण के रूप में मिले हैं।"

इस गवाह ने यह भी कहा था कि जब वह घर के बरामदे में गया तो उसने प्रतिवादी से पूछा कि क्या उसे शिकायतकर्ता से अवैध संतुष्टि मिली है और उसे पैसे दिखाने के लिए भी कहा। आरोपी कुछ नहीं बोला लेकिन

कुर्सी से उठा और घर के अंदर जाने की कोशिश की जिसे इंस्पेक्टर पी. डब्ल्यू. 12 ने करने से रोक दिया। गवाह ने आगे कहाः अधिकारी ने कहा, "आरोपी को कांपते हुए और तौलिया के नीचे कुछ करते हुए देखा गया था। आरोपी को तौलिया उतारने के लिए कहा। अभियुक्त ने तौलिया निकाल दिया। मैंने उसकी पहनी हुई धोती में उसकी कमर में कुछ उभरा हुआ देखा। मैंने उसे फिर से करेंसी नोट दिखाने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें धोती की तहों से बनाया जो उन्होंने पहनी थी। करेंसी नोट पेश करते समय आरोपी ने कुछ नहीं कहा।

मजिस्ट्रेट पी. डब्ल्यू. 13 के बयान के इन हिस्सों के खिलाफ कोई वास्तविक प्रतिपरीक्षा का निर्देश नहीं दिया गया था और न ही उच्च न्यायालय ने उनकी सही सराहना की है या उन्हें उचित महत्व दिया है। प्रत्यर्थी ने 11 जुलाई, 1952 को विशेष प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष रु प 1, 000 ये के लिए एक अहस्ताक्षरित नोट प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता के पक्ष में उसके द्वारा निष्पादित किया गया। 19 नवंबर, 1951 को जब पुलिस उपाधीक्षक द्वारा तलाशी ली गई तो वह नोट घर में नहीं मिला था, और यह नहीं बताया गया है कि नोट 1000 रुपये में क्यों बनाया जाना चाहिए था। जब वास्तव में भुगतान की गई राशि केवल रु 800 थी और प्रतिवादी ने पूर्ण विचार प्राप्त किए बिना शिकायतकर्ता को यह देने की पेशकश क्यों की।

ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की इन मुख्य विशेषताओं की उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से सराहना या उचित महत्व नहीं दिया गया है और हमारी राय में इस सवाल पर विद्वान न्यायाधीश का दृष्टिकोण कि क्या 800 रुपए एक अवैध संतुष्टि थी या एक ऋण ऐसा है कि निर्णय रामकृष्ण के मामले (1) में न्यायमूर्ति महाजन के शब्दों के भीतर आता है, यानी कि उच्च न्यायालय ने विकृत या अन्यथा अनुचित तरीके से कार्य किया है।

साक्ष्य और परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि लेन-देन ऋण का नहीं बल्कि अवैध संतुष्टि का था। इस निष्कर्ष को देखते हुए कि रु. 800 एक रिश्वत थी और ऋण नहीं, इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या इस मामले में ऋण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4 (1947 की धारा 2) या नहीं भीतर एक अवैध संतुष्टि होगी।। इसलिए हम इस अपील की अनुमति देते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश को दरकिनार करते हैं और कोयंबटूर के विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादी को उस अपराध के लिए दोषी ठहराने के आदेश को बहाल करते हैं जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। प्रत्यर्थी को अपने जमानत मुचलके के समक्ष समर्पण करना होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सपना राजपुरोहित द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।